सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 167 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार 24 जुलाई, 2026
मूल्य ₹ 3/-

मीठे वचन सब ओर सुख फैलाते हैं। किसी को भी वश में करने का ये एक मंत्र है। इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करें। तुलसीदास

हार के बावजूद भारत रैंकिंग में... 7 | कांग्रेस और टीवीके का डीएमके पर... 3 | भाजपा सरकार हिटलर की तरह... 2

आखिरकार झुकना ही पड़ा

छात्र संग्राम के दबाव में दूटी चुप्पी

अब डैमेज कंट्रोल की राह में सरकार

» वांगचुक का टूटा अनशन छात्रों से सवांद की शुरूआत

» विपक्ष बोला- अब सिर्फ बयान नहीं जवाबदेही चाहिए

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। किसानों के बाद छात्रों के आंदोलन ने भी सरकार को हठधर्मिता से हटकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। कई दिनों से सड़कों पर डटे छात्र संसद में लगातार हमलावर विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और बढ़ते जनदबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर आधी रात वीडियो संदेश जारी करना पड़ा।

ऐसा तब हुआ जब पूरे देश में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठना शुरू हो गये थे। जिस बेरहमी से छात्रों को पीटा गया और पुलिस ने बदसलूकी की उन वीडियो को देखकर देश की जनता का गुस्सा सांतवे आसमान पर है। अब सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया लेकिन विपक्ष और धरना दे रहे छात्र सरकार से पूछ रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में पेपर लीक नहीं होगा। छात्र इसे समाधान नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल बता रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि छात्र आंदोलन अब केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा बल्कि सरकार की जवाबदेही की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है।

छात्रों ने बदल दिया राजनीति का एजेंडा

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि छात्र आंदोलन ने देश की राजनीति का एजेंडा बदल दिया है। अब बहस केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है सवाल जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक विश्वसनीयता का भी है। सरकार अपनी घोषणाओं को समाधान बता रही है जबकि विपक्ष उन्हें देर से उठाया गया कदम मान रहा है। ऐसे में अंतिम फैसला जनता करेगी कि क्या यह निर्णायक कार्रवाई की शुरुआत है या फिर सिर्फ बढ़ते जनदबाव के बीच किया गया डैमेज कंट्रोल।

» राहुल-अखिलेश ने छात्र आंदोलन को दी राजनीतिक धार

» आधी रात के वीडियो के बाद तेज हुई इस्तीफे की मांग

आक्रमाक अंदाज में चला विपक्ष

इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष ने अपनी सभी राजनीतिक चालें बेहद आक्रामक अंदाज में चलीं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने विरोध को केवल प्रेस कान्फ्रेंस तक सीमित नहीं रखा। दोनों राजनेता सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हुए पुलिस कार्रवाई का सामना किया और प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर पूरे आंदोलन का राजनीतिक केंद्र बदल दिया। यही कारण है इस मुद्दे पर विपक्ष को पालिटिक्ल माइलेज मिलने के बाद सरकार दबाव में आयी और पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ तेज कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यदि मामला इतना गंभीर है तो शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दल लगातार यही मांग दोहरा रहे हैं कि केवल घोषणाएं नहीं बल्कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

पीएम मोदी का बयान पेपर लीक पर महज एक पट्टी

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने देशभर में नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर बढ़ते जनाक्रोश और विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडिया संदेश पर अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में प्रधानमंत्री की घोषणा के समय और तरीके पर सवाल उठाते हुए तीखी आलोचना की। पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इस मुद्दे पर बोलने या प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सीधे संवाद करने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान जारी किया है। संपादकीय में कहा गया कि यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पिछले महीनों से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और व्यापक सुधार की मांग को लेकर पुलिस की लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा है।

सीमित विरोध बन गया जनआंदोलन

दिलचस्प बात यह है कि जिस आंदोलन को शुरुआती दिनों में सीमित विरोध माना जा रहा था वही अब संसद सड़क और सोशल मीडिया तीनों जगह राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। एक ओर सरकार इसे कानून और व्यवस्था तथा सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के रूप में पेश कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे जनता के दबाव में आई सरकार की प्रतिक्रिया बता रहा है। यही वजह है कि अब लड़ाई केवल पेपर लीक की नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव की भी बन गई है। बीजेपी भी अब पूरी तरह पलटवार के मोड में दिखाई दे रही है। पार्टी ने विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए विरोध कार्यक्रमों की घोषणा की है। यानी अब मुकाबला केवल संसद के भीतर नहीं रहेगा बल्कि सड़कों और जनसभाओं में भी तेज होगा।

फेरबदल की शुरूआत बदले गये उच्च शिक्षा सचिव

देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और अनियमितताओं खासकर नीट से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। नियुक्ति समिति ने राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की विश्वसनीयता को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से जुड़े विवादों के बाद छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और व्यापक सुधारों की मांग की है। अधिकारियों के अनुसार उनकी तत्काल प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना हालिया परीक्षा विवादों से प्रभावित छात्रों का भरोसा बहाल करना और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना शामिल हो सकता है।

भाजपा सरकार हिटलर की तरह काम कर रही : अखिलेश यादव

सपा प्रमुख बोले- सादे कपड़ों में लाठीचार्ज वाले सामने लाएं, वरना मान लेंगे वे भाजपा कार्यकर्ता थे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर फिर एकबार हल्ला बोला है। उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सादे कपड़ों में लोगों से लाठीचार्ज कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी पहचान सार्वजनिक करे, अन्यथा उन्हें भाजपा कार्यकर्ता माना जाएगा। साथ ही नीट पेपर लीक, जौहर विश्वविद्यालय और शिक्षा व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हिटलर की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अन्याय करेगी, दबाव बनायेगी तो दबाव नहीं चलने वाला है। सरकार पर हिटलर की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिटलर भी अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहनाकर विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की पिटाई करवाता था। सोशल मीडिया और मीडिया में सादे कपड़े पहने लोगों द्वारा आन्दोलनकारियों पर लाठी चलाने की जो खबरें आ रही है वह जांच का विषय है। कहा कि सरकार इसकी सच्चाई बताएं, नहीं तो माना जाएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता वर्दी पहनकर पुलिस का डंडा लेकर छात्र-नौजवानों को लाठी मार रहे हैं।

जौहर विवि को बचाने की मुहिम में हम सब पूरी तरह से साथ हैं

जौहर विश्वविद्यालय को लेकर अखिलेश ने कहा कि इसे बचाने की मुहिम में हम सब पूरी तरह से साथ हैं। हर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, हम 'शिक्षा के मंदिर' को बचाने के लिए देश भर से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ आएं।

सरकार परिवारों की मांगों को पूरा करें

नई दिल्ली में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा लीक सरकार की गलती है। जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम लोग सदन में आवाज उठाते रहेंगे। नीट परीक्षा लीक के बाद जिन बच्चों की जान गयी है, सरकार उन परिवारों की मांगों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र और यूपी सरकार में पेपर लीक कराने की प्रतियोगिता चल रही है। आरोप लगाया कि पेपर लीक हो नहीं रहे, ये लीक कराये जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि क्या सरकार ने पुलिस को कपड़े फाड़ने की ट्रेनिंग दी है। आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में आए छात्रों-बच्चियों के कपड़े फाड़े, मारा-पीटा, लाठीचार्ज किया।

पूर्व सपा विधायक का कॉम्प्लेक्स ध्वस्त

जियामऊ में पूर्व सपा विधायक रामपाल यादव का कॉम्प्लेक्स एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। बतादें पास भाजपा का प्रदेश मुख्यालय बनना है। दस साल पहले भी इस पर बुलडोजर चलाया था, लेकिन तब इसे आधा तोड़कर ही छोड़ दिया था। उस वक्त पूर्व विधायक और उसके परिवार के सदस्यों ने भारी विरोध किया था, लेकिन इस बार कोई विरोध जताने नहीं पहुंचा। कॉम्प्लेक्स तोड़ने के लिए सात बुलडोजर मौके पर थे। जानकारों ने बताया कि अवैध कॉम्प्लेक्स सीतापुर की बिसवां विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा विधायक रामपाल यादव का था। जिस 3000 वर्गमीटर जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, वह नजूल की जमीन थी। एलडीए ने अप्रैल 16 में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। जमीन खाली होने के बाद अब यहां 500 मीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसमें जियामऊ के पास पेट्रोल पंप की ओर 300 मीटर और जियामऊ इलाके की ओर 200 मीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।

वोट की ताकत से हासिल करें राजनीतिक सत्ता : मायावती

» बसपा की रैली में टिकट के दावेदार दिखाएंगे दम, 10 लाख की भीड़ जुटाने की योजना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बसपा प्रमुख व यूपी सीएम ने कहा है कि लोग आंदोनल की बजाए वोट की ताकत से सत्ता को हासिल करें।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) संस्थापक कांशीराम के 9 अक्तूबर को होने वाले परिनिर्वाण दिवस पर राजधानी लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर महारैली आयोजित करेगी। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण पार्टी ने रैली को शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनाया है। संभावित उम्मीदवारों को अधिक से अधिक समर्थकों के साथ रैली में पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भीड़ जुटाने वाले दावेदारों के टिकट पर अंतिम फैसला हो सकता है। रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अगले सप्ताह प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बसपा अध्यक्ष मायावती आवश्यक दिशा-निर्देश देंगी। पिछले वर्ष 9 अक्तूबर की रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से संगठन में उत्साह बढ़ा था। उसी मंच से मायावती ने आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ने का एलान किया था।

10 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद

इस बार भी मायावती के कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और संगठनात्मक संदेश देने की संभावना है। पार्टी का दावा है कि रैली में 10 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के आने का अनुमान है। बसपा मानती है कि यदि रैली में अपेक्षित भीड़ जुटती है तो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने और राजनीतिक संदेश देने में यह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

गोरक्षा के लिए आवाज उठाने पर मिल रही बुलडोजर की धमकी : अविमुक्तेश्वरानंद

» शंकराचार्य ने योगी सरकार पर साधा निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । गोरक्षा के लिए निकली धर्मयुद्ध यात्रा में बाधा डालने और समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा।

उन्होंने दावा किया कि कई कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के लिए उनके घरों में ही नजरबंद रखा गया। कुछ समर्थकों को उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी तक दी जा रही है। यात्रा के दौरान भी कई स्थानों पर रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं मिलने के कारण समर्थकों को रात सड़क पर बितानी पड़ी।

शंकराचार्य ने कहा कि प्रशासन के असहयोग के कारण गो गर्जन अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्र म अब डिजिटल माध्यम से आयोजित करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए 4.64 लाख रुपये से अधिक शुल्क जमा करने के बावजूद अंतिम समय तक प्रशासन की ओर से स्पष्ट अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने और प्रशासन के रवैये पर आपत्ति जताने की बात कही।

403 विधानसभा क्षेत्रों से उठेगी गोरक्षा संकल्प की आवाज

शंकराचार्य ने बताया कि पहले 24 जुलाई शु क्र वार को आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति उपवन में दोपहर 12 बजे गो गर्जन अक्षौहिणी संकल्प का सार्वजनिक आयोजन प्रस्तावित था। अब यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से होगा। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में लोग एकत्र होकर गो रक्षा का संकल्प लेंगे। दोपहर 12 से दो बजे के बीच गो माता की रक्षा को लेकर संकल्प लेने के साथ आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी।

स्टेटहुड की मांग से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस : वहीद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कश्मीर। पुलवामा विधायक वहीद उर रहमान पारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली स्थित जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टेटहुड की मांग के जरिए पार्टी ने अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली के मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की है।

उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने इन मुद्दों पर पहले ही आश्वासन दिया है और जम्मू-कश्मीर के वास्तविक हितों से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री उस्मान माजिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए इसे लोकप्रियता वापस पाने की कोशिश और राजनीतिक ड्रामा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेकां ने आर्टिकल 370 और 35ए की बहाली के चुनावी वादों को छोड़ दिया है और अब केवल स्टेटहुड के मुद्दे पर राजनीति कर रही है।

गलतियां नहीं मान रही सरकार : ओवैसी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने युवाओं का अपमान करने और अपनी गलतियों को न मानने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। ओवैसी ने कहा कि सरकार युवाओं को नज़रअंदाज़ करती है और उनसे बातचीत करने से बचती है।

उन्होंने कहा कि आप छोटे बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें दो घंटे तक घर पर बिठाए रखते हैं। आप उनसे बात नहीं करते, बल्कि उन्हें अपमानित करते हैं। आपको उनसे बात करना सीखना चाहिए। यह सब आपकी, यानी सरकार की वजह से हो रहा है। ओवैसी ने अलग-अलग संकटों के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने पर सरकार की आलोचना की और उनसे आरोप-प्रत्यारोप का खेल बंद करके अपनी गलतियाँ मानने को कहा। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है, उसके लिए आप विपक्ष को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन्हें आपको मानना चाहिए। आप तो उन्हें मान भी नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पास

भारी बहुमत है और आप हम सबको दबा देंगे। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप इसे कम आंक रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को, कई विपक्षी सदस्यों ने संसद परिसर में मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन किया और परीक्षा पेपर लीक को लेकर देश भर में हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की। एनडीए और इंडिया हुआ, क्योंकि दोनों पक्षों ने मकर द्वार पर अलग-अलग मुद्दों पर एक साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

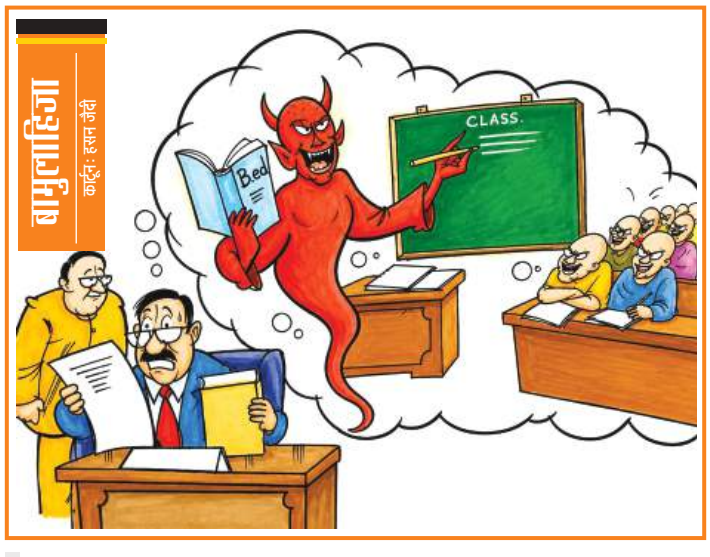

योगी सरकार युवाओं को उच्चशिक्षा में नौकरी नहीं दे पाई : डॉ. राय

» उच्च शिक्षा के कॉलेजों में शिक्षकों का बिना वेतन के गुजर रहा जुलाई का महीना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। पिछले चार वर्षों में प्रदेश की योगी सरकार एक भी युवा को उच्च शिक्षा में नौकरी नहीं दी पाई है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 22 में जारी किए गए विज्ञापन संख्या 51 के तहत 13 विषयों के 910 पदों पर भर्ती प्रकिया अभी तक अधर में लटकी हुई है। इस प्रकार पिछले चार वर्षों में यह सरकार एक भी युवा को उच्च शिक्षा में नौकरी नहीं दे पाई है।

कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के चेयरमैन-पूर्व मंत्री डॉ. सीपी राय ने आज जारी बयान में कहा है कि नए शिक्षा आयोग के गठन व अन्य कारणों से यह परीक्षा अप्रैल 25 में संपन्न हुई।

इस परीक्षा में भारी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थियों द्वारा लगातार धरना दिया गया और कोर्ट का सहारा लिया गया। बाद में शासन ने और आयोग ने अपनी गलती मानी और यह माना की पांच विषयों का पेपर आउट हुआ था और इसलिए पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। बाद में पुन: परीक्षा 19 - 20 अप्रैल 26 को संपन्न कराई गई जिसका साक्षात्कार 22 जुलाई से 13 अगस्त 26 तक होना था। लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह मांग रखी गई कि यदि पांच विषयों में नकल हुई है या पेपर आउट हुआ है तो केवल उन्हीं की परीक्षा कराई जाए बाकी विषयों का साक्षात्कार पुराने परीक्षा परिणाम पर ही कराया जाए। इसी प्रकरण को लेकर 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जो साक्षात्कार 22 जुलाई से शुरू होना था वह भी स्थगित कर दिया गया है। डॉ0 राय ने कहा कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों का कहना है कि कोई भी व्यवस्था बनाने से पहले वेतन की निरंतरता का ख्याल रखा जाना चाहिए था।

तमिलनाडु में सियासी कोहराम

कांग्रेस और टीवीके का डीएमके पर वार

» केंद्र सरकार के खिलाफ खुला
» नया मोर्चा
थलपति विजय आंदोलन पर खामोश, अब नीट
» एग्जाम पर उठाए सवाल
केंद्र के साथ स्टालिन
» को भी उलझाया
विजय की टीवीके के बाद स्टालिन बोले- खत्म करो नीट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच जहां पूरे देश में सियासी माहौल गर्म है वहीं तमिलनाडु में अलग तरहे की राजनीति देखने को मिल रही कुछ मुद्दो को लेर जहां डीएमके पर टीवीके व कांग्रेस हमलावर हैं। उधर भाजपा से डीएमके का संबंध मीठे होने के संकेत लग रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक और 21 छात्रों के सुसाइड के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का दिल्ली में आंदोलन चल रहा है।

कांग्रेस ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज की है। सीएम विजय जहां प्रोटेस्ट पर खामोश हैं लेकिन नीट पर उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया है। जिसका एम के स्टालिन ने मजबूती से समर्थन किया है। विजय ने केंद्र और स्टालिन दोनों को उलझा दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने परिसीमन बिल पर डीएमके के रुख में बदलाव को लेकर आलोचना की है, यह संदेह जताते हुए कि पार्टी एक देश, एक चुनाव के लालच में है, उन्होंने चेतावनी दी कि यह डीएमके के लिए चुनावी तौर पर महंगा साबित होगा।

थलपति विजय की जीत में जेन-जी का बड़ा रोल

डीएमके तमिलनाडु और केंद्र में लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ रही है। अभी की स्थिति में डीएमके की गठबंधन टूट चुका है जबकि टीवीके कांग्रेस की दोस्ती नई-नई है। हालांकि डीएमके और टीवीके दोनों नीट के मुद्दे पर एक ही स्टैंड रख रही हैं। थलपति विजय की जीत में जेन-जी का बड़ा रोल माना गया था। विजय की टीवीके के नीट को खत्म करने की मांग के बाद डीएमके प्रमुख ने वहीं स्टैंड लिया है। 18 तक इसका आयोजन सीबीएसई द्वारा किया गया था 7 लेकिन 2019 से इसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को सौंप दी गई।

स्टालिन ने बोला- मैंने पहले कहा था नीट खत्म हो

एम के स्टालिन ने लिखा है कि नई दिल्ली में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन ने अब पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमने सबसे पहले चेतावनी दी थी कि नीट को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो सकें। इसीलिए डीएमके ने शुरू से ही नीट का विरोध किया है और लगातार इससे जुड़े खतरों के बारे में बताया है। स्टालिन ने लिखा है कि तमिलनाडु जिसने सामाजिक न्याय की रक्षा में भारत का नेतृत्व किया और पहले संवैधानिक संशोधन का रास्ता तैयार किया, उसकी बस एक ही मांग है कि नीट को खत्म किया जाए। स्टालिन ने लिखा है कि किसी भी दूसरी मांग से ज्यादा जरूरी है कि नीट को खत्म करना इन विरोध-प्रदर्शनों का मुख्य मुद्दा हो। सिर्फ **NEET** को खत्म करने से ही इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान मिल पाएगा, हालांकि उन्होंने सीजेपी की प्रिंसिपल डिमांड धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा है।

नीट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए : थलपति विजय

तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय ने कहा था कि नीट को पूरी तरह से खत्म कर दो। विजय की अगुवाई वाली टीवीके ने कहा था कि टीवीके ने कहा कि नीट परीक्षा के कारण हर साल छात्रों को होने वाला नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार से नीट परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करने की पुरजोर मांग करते हैं। इस मांग का डीएमके चीफ एम के स्टालिन ने भी समर्थन किया है। डीएमके पहले ही नीट परीक्षा के तौर-तरीकों को लेकर मुखर रही है।

कांग्रेस ने डीएमके को घेरा

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को अहम विधायी मामलों पर अपना रुख बदलने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की आलोचना की और कहा कि पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की सार्वजनिक जांच होनी चाहिए, जिसमें कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिट और संसदीय चर्चा शामिल हो। **DMK** के रुख पर बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि आपको डीएमके से ही पूछना होगा कि वे अपना स्टैंड क्यों बदल रहे हैं। मेरी राय में, उन्हें एक देश, एक चुनाव का लालच दिया जा रहा है। वे जल्द से जल्द एक और चुनाव कराने की जल्दी में हैं। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर **DMK** उस रास्ते पर चलती है, तो अगले चुनावों में उनका हाल हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से भी बुरा होगा।

डीएमके को अपना पुराना विरोध जारी रखना चाहिए: कार्ति चिदंबरम

प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डीएमके अपना पुराना विरोध जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि **DMK** का क्या रुख है; आपको उनसे पूछना चाहिए। पिछली बार उन्होंने विधेयक का विरोध किया था, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी वे विधेयक का विरोध करेंगे। चिदंबरम ने अपने विरोध का कारण बताते हुए कहा कि भले ही सीटों में बढ़ोतरी प्रतिशत के हिसाब से बराबर लगे, लेकिन असल संख्या के मामले में संसद में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच का अंतर बढ़ा। उन्होंने कहा कि कागज पर तो ऐसा लगता है कि सबको प्रतिशत के हिसाब से बराबर बढ़ोतरी मिल रही है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में असल संख्या मायने रखती है। अभी तमिलनाडु और पुडुचेरी के पास 40 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं। तो,

तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश के बीच का अंतर 400 है। लेकिन अगर सीटों को 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीटें 60 हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश की 120। ऐसे में अंतर 60 हो जाएगा। इसलिए राजनीति में असल संख्या मायने रखती है। यह सिर्फ प्रतिशत की बात नहीं है, क्योंकि भारत के उत्तरी राज्यों की बराबरी करने के लिए दक्षिणी राज्यों को बहुत ज्यादा काम करना होगा। दक्षिणी राज्यों की आबादी कम है और उन्होंने टैक्स में ज्यादा योगदान दिया है, फिर भी लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या कम हो जाएगी।

लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने से संसदीय बहसों की असरदारता कम हो जाएगी

उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने से संसदीय बहसों की असरदारता कम हो जाएगी। चिदंबरम ने कहा कि इसके अलावा, सदन में 543 सदस्य होने पर भी हमें बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। 815 सदस्य होने पर बोलने के लिए और भी कम समय मिलेगा। स्पीकर हम सभी के नाम नहीं जानते हैं, और जो 300 अतिरिक्त सदस्य आएंगे, उनके नाम तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं होंगे। ऐसे में, सदन चीन की तरह बस एक स्टैम्पिंग हाउस बनकर रह जाएगा। एक बड़ी संसद बेअसर संसद होगी।

2016 में हुई नीट परीक्षा की बहाली

मेडिकल (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट (नेशनल एलिजबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) की शुरुआत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) और केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस परीक्षा का प्रस्ताव 2010 में संसद में लाया गया था और पहली बार देश भर में इसका आयोजन 5 मई 13 को किया गया था। हालांकि 13 में पहली बार आयोजित होने के बाद कानूनी विवादों और राज्यों की असहमति के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद 16 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद नीट को फिर से बहाल किया गया और 17 से इसे देश की एकमात्र अनिवार्य मेडिकल प्रवेश परीक्षा बना दिया गया। 2010 में संसद में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010 तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद की ओर से स्वास्थ्य राज्य मंत्री एस. गांधीसेलवन द्वारा पेश किया गया था।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

इस तरह से तो गिरती रहेगी देश की साख

इस समय देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से सरकारी दमन हो रहा है उससे भारत की लोकतंत्र की छवि खराब हो रही है वही चिंतनीय है। इसबीच दुनिया में भारत के महानगरों की यह भयावह तस्वीर ने लोगों को शर्मिन्दा होने को विवश कर दिया। कभी पासपोर्ट तो कभी हंगर इंडेक्स, फ्री मीडिया जैसे मामलों में भारत पिछड़ रहा है। अब तो रहने वाले शहरों के मामले में भी भारत की रैंकिंग गिर रही है। केंद्र और राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए वादे खोखले साबित हुए हैं। पिछले साल देश भर के 26 शहरों में कम से कम 5,500 लोग दशकों पुरानी खराब पाइपलाइनों के कारण सीवेज से दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए थे और ये तो केवल दर्ज और रिपोर्ट किए गए मामले हैं। क्या स्मार्ट सिटी का अर्थ केवल चौड़ी सड़कें, चमकदार भवन और आकर्षक परियोजनाएं हैं? क्या स्मार्ट शहर वह नहीं होना चाहिए जो सामान्य से अधिक बारिश को भी सहजता से संभाल सके? यदि अरबों रुपये जल निकासी, सड़क निर्माण और शहरी विकास पर खर्च हो रहे हैं, तो पहली तेज बारिश में ही सड़कें नदी और चौराहे तालाब क्यों बन जाते हैं?

क्या विकसित भारत केवल बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे और गगनचुंबी इमारतों से बनेगा? या फिर उसकी पहचान ऐसी मजबूत बुनियादी व्यवस्था से होगी जो हर मौसम में नागरिकों को सुरक्षित और सुगम जीवन दे सके? पिछले वर्ष शहरी कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि घोषित राशि से 40 प्रतिशत कम थी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी (रहने योग्य) इंडेक्स 26 में उजागर हुई है। दुनिया के 173 शहरों का स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचा, पर्यावरण, स्थिरता और सांस्कृतिक सुविधाओं जैसे प्रमुख मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। जिसमें देश की राजधानी नई दिल्ली 120वें स्थान पर रही, जबकि आर्थिक राजधानी मुंबई 121वें स्थान पर कायम रही। दक्षिण भारत के प्रमुख महानगर चेन्नई को 123वां और बेंगलुरु को लिवेबिलिटी रैंकिंग में 127वां स्थान मिला है। यह देश के सत्तारुढ़ दलों के नेताओं के लिए बेशक शर्म का विषय नहीं हो, किन्तु रैंकिंग की इस हालत से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हुई है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इन शहरों की रैंकिंग में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। यह स्थिति दर्शाती है कि तेज आर्थिक विकास के बावजूद भारतीय महानगरों में जीवन गुणवत्ता, यातायात, प्रदूषण, सार्वजनिक सेवाओं और शहरी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां और भारी भ्रष्टाचार अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई हैं।

“ कभी पासपोर्ट तो कभी हंगर इंडेक्स, फ्री मीडिया जैसे मामलों में भारत पिछड़ रहा है। अब तो रहने वाले शहरों के मामले में भी भारत की रैंकिं ग गिर रही है। केंद्र और राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए वादे खोखले साबित हुए हैं।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

लोकतंत्र में सख्ती नहीं, उदार संवाद उपयोगी

विश्वनाथ सचदेव

वह मां अपनी तेरह-चौदह साल की बच्ची को लेकर राजधानी दिल्ली के 'प्रदर्शन-स्थल' जंतर-मंतर में आई थी। एक पत्रकार ने जिज्ञासा की तो उस मां ने कहा था, 'मैं अपनी बेटी को एक वास्तविकता से परिचित कराने लाई हूं— कल उसे भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी।' वह मां अकेली नहीं थी, जो अपनी संतान के बारे में इस तरह सोच रही थी। और वह बच्ची भी अकेली नहीं थी, जो अपने भीतर संघर्ष का एक जज्बा लेकर वहां पहुंची थी। उस दिन, जब सड़क से संसद तक पहुंचने की एक होड़-सी लगी थी युवाओं में, तो यह जज्बा अपने पूरे उफान पर था। हां, उस दिन वहां राजधानी दिल्ली के ही नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों से भी हजारों 'कॉकरोच' इकट्ठे हुए थे।

ये 'कॉकरोच' पिछले लगभग एक माह से अधिक समय से अपने अधिकारों के लिए और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जंतर-मंतर पर बैठकर संघर्ष कर रहे थे। इस शांतिपूर्ण संघर्ष में कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कारगर अस्त्र-अनशन को अपना हथियार बनाया था। लद्दाख से आए सोनम वांगचुक का नेतृत्व मिला था इन युवाओं को। एक मांग थी इन सबकी-देश की शिक्षा-व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाने वाली सरकार की नीतियों में बदलाव चाहते थे वे। देश का शिक्षामंत्री इन नीतियों का प्रतीक बना और देश के युवा यह मांग कर रहे थे कि वे स्थिति की जवाबदेही स्वीकार करें और अपने पद से इस्तीफा दें। पर देश की सरकार को यह स्वीकार नहीं था। ये युवा 6 जून से धरना दे रहे थे। हैरानी की बात यह है कि सरकार को न धरने की परवाह थी और न ही भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों की। शायद सरकार यह मानकर चल रही थी कि वे प्रदर्शनकारी थक जाएंगे और आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। यदि यही सरकार की सोच थी, तो वह गलत थी। सही क्या था, यह सरकार और देश ने संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन देखा। हजारों की संख्या में देश के छात्र-युवा सरकार को यह दिखाने के लिए एकत्र हुए थे कि 'नीट' जैसी परीक्षाओं में हुए घोटालों से वे अपने भविष्य को अंधकारमय पा रहे हैं।

देखा जाए तो यह आंदोलन युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है। सरकार ने इसे बहुत हल्के में लिया था। हो सकता है, कल सरकार की यह

असंवेदनशीलता युवाओं को थका दे, पर यह सवाल अपनी जगह बना रहेगा कि जनतांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार अपने ही युवाओं के प्रति इस तरह का रवैया कैसे अपना सकती है? हैरानी की बात यह भी है कि एक महीने से भी अधिक समय से चल रहे इस आंदोलन के प्रति हमारे मुख्यधारा के मीडिया ने भी लंबे समय तक उसे वह महत्व नहीं दिया, जो दिया जाना चाहिए था। हां, संसद तक पहुंचने की कूच वाले दिन हमारा मीडिया जरूर कुछ सक्रिय हुआ और तब देश को पता चला कि युवाओं का आक्रोश सचमुच उफान पर था। संयोग की बात है कि जब राजधानी दिल्ली में देश के युवा अपनी व्यथा का प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे, तभी हमारे युवा वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की खोज की कहानी में अपना योगदान दर्ज करवाया। प्रधानमंत्री ने इन युवा प्रतिभाओं को बधाई देते हुए देश की युवा शक्ति की उपलब्धियों और संभावनाओं का बखान किया। प्रशंसा के पात्र हैं हमारे ये युवा वैज्ञानिक, पर उन युवाओं पर प्रधानमंत्री की निगाह क्यों नहीं गई, जो राजधानी में संसद के दरवाजे तक पहुंचकर अपनी पीड़ा उन तक पहुंचाना चाहते थे? जब युवाओं की टोलियां संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, तो एक तरफ संसद भवन के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और दूसरी ओर लाठियों तथा आंसू गैस के गोलों से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मीडिया की सहायता से सारे देश ने राजधानी की सड़कों पर छात्रों-युवाओं पर पुलिस की मार के दृश्य देखे। लाठीचार्ज में सैकड़ों छात्र-युवा घायल हो गए। पुलिस की ओर से इस हंगामे में घायल पुलिसकर्मियों की संख्या भी बताई गई। नहीं होना चाहिए था यह न छात्र घायल होने चाहिए थे, न पुलिस वाले। पर सवाल, जो पूछा जाना चाहिए, वह यह है कि यह स्थिति क्यों आई?

स्थिति के इस स्तर तक पहुंचने के बाद सरकार की ओर से युवाओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। यह काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? हैरानी की बात है कि इस सारे हंगामे के दौरान सरकार को न सड़कों पर नारे लगाते युवा दिखे और न ही भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और उनके युवा साथी। हैरानी तो इस बात की भी है कि सरकार की ओर से यह कहना जरूरी समझा गया कि आंदोलनकारियों ने पहली बार बातचीत की पेशकश की है। क्या सरकार को इस बारे में पहल करने से किसी ने रोक रखा था? क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि वह आंदोलन कर रहे युवाओं तक पहुंचकर उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करती।

मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर बंटवारा

डॉ. सुधीर कुमार

क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जो जमीन हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है, वह वास्तव में किसकी है? क्या वह केवल कागजों पर दर्ज हमारी एक निजी संपत्ति है जिसे हम जब चाहें, जैसे चाहें बेच दें? या फिर, उस मिट्टी के कण-कण पर हमारे पूरे परिवार, हमारे भाई-बहनों और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी कोई नैतिक और कानूनी हक है? अक्सर गांवों, कस्बों और यहां तक कि शहरों में भी हमने देखा है कि जमीन के टुकड़े को लेकर घर के रिश्ते कैसे बिखर जाते हैं। किसी ने अपनी पुश्तैनी जमीन बिना परिवार से पूछे किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दी, और बस इसी एक फैसले से सालों-साल चलने वाली कलह की नींव पड़ गई। भाई-भाई से अलग हो गया, संयुक्त परिवार टूट गए और जो जमीन कभी समृद्धि का प्रतीक थी, वह कड़वाहट और अदालती मुकदमों की जड़ बन गई।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 'महिंदर और अन्य बनाम पूरन सिंह' (14 जुलाई, 2026) मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो भारत के हर उस परिवार के लिए एक 'सुरक्षा कवच' बन गया है, जिसके पास खेती की जमीन है। यह फैसला केवल कानूनी किताबों की कोई सूखी शब्दावली नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों की सामाजिक एकता को बचाने की कोशिश है, जिनकी जड़ें आज भी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। यह कानूनी संघर्ष निचली अदालतों से शुरू हुआ था। विवाद का मुख्य मुद्दा बहुत सरल लेकिन गहरा था क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22, खेती की जमीन पर भी लागू होती है? निचली अदालतों में एक लंबा तर्क चला कि खेती की जमीन आम संपत्तियों से अलग होती है। कुछ लोगों का कहना था कि यह आजीविका का साधन है, इसलिए इस पर मालिक का पूरा नियंत्रण होना चाहिए और उत्तराधिकार के सामान्य कानून इस पर लागू नहीं होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम शंकाओं को एक झटके में खत्म कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून की नजर में पुश्तैनी संपत्ति का स्वरूप नहीं बदलता। चाहे वह रहने का घर हो या खेती का खेत, यदि वह विरासत में मिली है, तो उसके प्रति कानूनी दायित्व समान हैं। कोर्ट ने यह संदेश दिया कि जमीन की प्रकृति बदल सकती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी का स्वरूप नहीं। सरल शब्दों में कहें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 का मतलब है- 'परिवार का पहला हक'। यह धारा कहती है कि यदि कोई वारिस विरासत में मिली संपत्ति का अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो वह सीधे किसी अनजान व्यक्ति या बाहरी खरीदार के पास नहीं जा सकता। इसे 'प्रिएम्पशन का अधिकार' कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बाहरी व्यक्ति को जमीन बेचने की स्वतंत्रता केवल तभी मिलती है जब परिवार का कोई भी सदस्य उसे खरीदने में रुचि न रखे या असमर्थ हो। यह कानूनी प्रावधान परिवार की पुश्तैनी विरासत को बाहरी हस्तक्षेप से बचाकर उसकी सामाजिक एकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। यूरोप के जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में खेती की जमीन को 'अविभाज्य इकाई' मानकर कड़े कानूनों के जरिए उसे परिवार के भीतर ही सुरक्षित रखा जाता है, ताकि पुश्तैनी परंपराएं बनी रहें।

इसके विपरीत, अमेरिका में व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है और जमीन बेचने की पूरी आजादी है, लेकिन वहां भी संपन्न परिवार अपनी विरासत को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए 'फैमिली ट्रस्ट' और 'कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स' जैसी कानूनी व्यवस्थाओं का समझदारी से उपयोग करते हैं। भारत का कानून इन दोनों के बीच का एक संतुलन है। हम व्यक्ति की आजादी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन परिवार और समाज की एकता को भी बहुत महत्व देते हैं। यह भारतीय कानून की खूबी है कि वह हमें व्यक्तिगत अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही हमें यह याद दिलाता है कि हम एक सामाजिक इकाई का हिस्सा हैं। यह हमें दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले एक अधिक मानवीय चेहरा प्रदान करता है, जो रिश्तों को सिर्फ पैसे से ऊपर रखकर देखता है। इस तरह, यह कानून न केवल विवादों को जन्म लेने से रोकता है, बल्कि परिवार के भीतर आपसी संवाद और रिश्तों की मजबूती को भी अनिवार्य बनाता है। नि:संदेह, जमीन का संरक्षण केवल संपत्ति का अधिकार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने का एक पुनीत कर्तव्य है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि कानून की असली सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब वह न्याय प्रदान करने के साथ-साथ हमारी सामाजिक जड़ों को भी सींचता रहे।

आज के दौर में जब संयुक्त परिवार सिमट रहे हैं और भौतिकवाद हावी हो रहा है, यह फैसला एक संजीवनी का कार्य करता है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि परिवार कोई कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि विश्वास और साझा दायित्वों का समूह है। संपत्ति के बंटवारे के समय न्याय केवल कागजी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर भी होना चाहिए। अगली बार जब आप अपने पुश्तैनी खेतों की मेड़ पर खड़े हों, तो याद रखिएगा कि वह जमीन मात्र मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार का सांझा इतिहास है। यदि अब आपसे कोई कहे कि 'मेरी जमीन, मैं किसी को भी बेचूं,' तो उन्हें धारा 22 की यह सरल सीख अवश्य याद दिलाइए - 'कानून के अनुसार, पहला हक घर का, बाद में बाहर का; पहले परिवार को पूछिए, फिर बाहर देखिये!' यह कानून न केवल जमीन को सुरक्षित रखेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बीच रिश्तों की डोर को भी और मजबूत करेगा।

खीरे से गर्मी में बनाएं रिफ्रेशिंग मॉकटेल ड्रिंक्स

गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपको कुछ स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग पीने को मिल जाए, तो बात ही अलग हो जाती है। खीरा एक ऐसा सुपरफूड है जो पानी से भरपूर होता है और शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। आमतौर पर खीरे का इस्तेमाल सलाद में किया जाता है, लेकिन इससे आप बेहद स्वादिष्ट मॉकटेल ड्रिंक्स भी बना सकते हैं? ये ड्रिंक्स न सिर्फ आपको गर्मी से राहत देंगे बल्कि आपके शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करेंगे। इन मॉकटेल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने में ज्यादा समय या मेहनत नहीं लगती। कुछ आसान सामग्री और 5-10 मिनट में आप घर पर ही कैफे-स्टाइल ड्रिंक्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस समर में कुछ नया और हेल्दी ट्राय करना चाहते हैं, तो ये 5 खीरे के मॉकटेल आपके लिए परफेक्ट हैं। खीरे से बने ये मॉकटेल्स न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। इस गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स की जगह इन हेल्दी विकल्पों को अपनाएं और खुद को रखें कूल, फ्रेश और एनर्जेटिक।

नींबू-खीरा रिफ्रेशर

यह विटामिन सह से भरपूर ड्रिंक इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसे बनाने के लिए एक ब्लेंडर (मिक्सी) में खीरे और पुदीने की पत्तियों को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें? इस मिश्रण को एक महीन छलनी या सूती कपड़े की मदद से छान लें ताकि खीरे का शुद्ध रस मिल सके? एक बड़े जग में खीरे का यह रस निकालें। इसमें नींबू का रस, ठंडा पानी, चीनी/शहद और काला नमक मिलाएं? गिलासों में बर्फ के टुकड़े डालें, रिफ्रेशर डालें और ऊपर से नींबू के स्लाइस व पुदीने की पत्तियों से सजाकर तुरंत ठंडा परोसें?

खीरा-शहद ड्रिंक

खीरे के जूस में शहद और ठंडा पानी मिलाएं। यह ड्रिंक नेचुरल एनर्जी देता है और स्किन के लिए भी फायदेमंद है। गर्मियों में आपको रिफ्रेश भी रखेगा।

खीरा-फ्रूट मिक्स कूलर

गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड और तरोताजा रखने के लिए खीरा-फ्रूट मिक्स कूलर एक बेहतरीन और पौष्टिक ड्रिंक है। इसे बनाने में 10 मिनट से भी कम समय लगता है और आप इसे घर पर मौजूद ताजे फलों के साथ आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह ड्रिंक स्वाद के साथ-साथ हाइड्रेशन का पावरहाउस है। अगर आप पाचन और कब्ज जैसी समस्या से परेशान हैं तो खीरे को डाइट में शामिल कर सकते हैं। खीरे के जूस के सेवन से ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी समस्या में आराम मिल सकता है। इसे बनाने के लिए ब्लेंडर में कटे हुए खीरे, फलों और पुदीने की पत्तियों को थोड़े से पानी के साथ डालकर स्मूद ब्लेंड कर लें। एक महीन छलनी की मदद से रस को किसी बड़े बाउल या जग में छान लें ताकि पल्प और बीज अलग हो जाएं। इस छने हुए जूस में नींबू का रस, काला नमक और शहद मिलाएं। गिलासों में बर्फ के टुकड़े डालें, ऊपर से ठंडा खीरा-फ्रूट मिक्स कूलर डालें अब इसमें काला नमक मिलाएं। आइस क्यूब मिलाकर ठंडा कर सकते हैं। और ताजे पुदीने की पत्तियों से सजाकर तुरंत सर्व करें।

ककड़ी-पुदीना कूलर

यह ड्रिंक तुरंत ताजगी देता है और बॉडी को कूल रखता है। इसे बनाने के लिए एक ब्लेंडर (मिक्सी) में ककड़ी के टुकड़े, पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस, चीनी और काला नमक डालें। थोड़ा सा पानी डालकर इसे तब तक पीसें जब तक यह बिल्कुल चिकना न हो जाए। एक बारीक छलनी की मदद से इस मिश्रण को छान लें, ताकि ककड़ी और पुदीने के मोटे कण अलग हो जाएं। एक लंबे गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें। इसमें तैयार किया गया ककड़ी-पुदीना बेस डालें और ऊपर से ठंडा पानी या सोडा भरें। पुदीने की पत्ती और ककड़ी के पतले स्लाइस से सजाकर तुरंत ठंडा परोसें। गर्मियों में इस ड्रिंक को अपनी पसंद के अनुसार मीठा, खट्टा या नमकीन एडजस्ट किया जा सकता है। आप इस ड्रिंक को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इस कूलर में अदरक डालकर एक नया स्वाद तैयार कर सकते है या इसमें वोदका या जिन मिलाकर इसे कॉकटेल के रूप में भी बना सकते हैं।

स्पार्कलिंग कुकुंबर मॉकटेल

कद्दूकस किया हुआ या पतले स्लाइस खीरे के काट लें। अब पुदीने की पत्तियों के साथ खीरे को मिलाकर अच्छे से मैश कर लें। मिठास के लिए शहद मिला सकते हैं। फिर एक गिलास में ये मिश्रण डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े और सोड़ा या स्पार्कलिंग वाटर डालें। चम्मच से ड्रिंक को मिलाकर सर्व करें। यह ड्रिंक पार्टी के लिए परफेक्ट और बेहद स्टाइलिश लगता है।

हंसना मना है

एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया। टॉयलेट से जिन्न प्रकट हुआ.. जिन्न ने लड़की को गोल्ड का फोन दिया और कहा ये लो तुम्हारा फोन, लड़की ने 'कुल्हाड़ वाली कहानी सुन रखी थी। इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा: ये सोने का फोन मेरा नहीं है। जिन्न: पगली रुलाएगी क्या? धो के देख तेरा ही है।

राजू पहाड़ों पर पैराशूट बेच रहा था, ग्राहक: अगर पैराशूट नहीं खुला तो? राजू: तो आपके पूरे पैसे वापिस।

पति: तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो, जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं। और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं, पत्नी: तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी जिंदगी पर।

मां: बेटा क्या कर रहे हो? बेटा: पढ़ रहा हूं, मां: शाबाश! क्या पढ़ रहे हो? बेटा: आपकी होने वाली बहु के एसएमएस। दे थप्पड़, दे थप्पड़!

साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला- भाईसाहब आप बहुत किस्मत वाले हो? आदमी: एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे हो? साइकिल वाला- आज छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूं नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूं?

कहानी | एक सत्संग ऐसा भी

एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। उनके घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता ने पूछा सेठजी आप रोज कहां जाते है। सेठजी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते है। तोता बोला संत महात्मा से पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। सेठजी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछा कि महाराज हमारे घर जो तोता है उसने पूछा हैं कि वो आजाद कब होगा? संत जी ऐसा सुनते हीं बेहोश हो गये। सेठजी संत की हालत देख कर चुप-चाप वहां से निकल जाते है। घर आते ही तोता सेठजी से पूछता है कि संत ने क्या कहा। सेठजी कहते है कि तेरे किस्मत ही खराब है जो तेरी आजादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता बोला कोई बात नहीं सेठजी में सब समझ गया। दूसरे दिन सेठजी सत्संग में जाने लगे तब तोता जानबूझ कर बेहोश होकर गिर जाता हैं। सेठजी मरा मानकर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकालते है, तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठजी को पूछते है कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना अब वो कहां हैं। सेठजी बोले आज वो जानबुझ कर बेहोश हो गया, मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठजी से कहा की देखो तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह-माया के पिंजरे में फंसे हुए हो और उस तोते को देखो बिना सत्संग में आये मेरा एक इशारा समझ कर आजाद हो गया।

शिक्षा- इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सत्संग में तो जाते हैं ज्ञान की बाते करते हैं या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता हैं। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते है जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता हैं। जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिये और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किये हुए हैं उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए।

7 अंतर खोजें

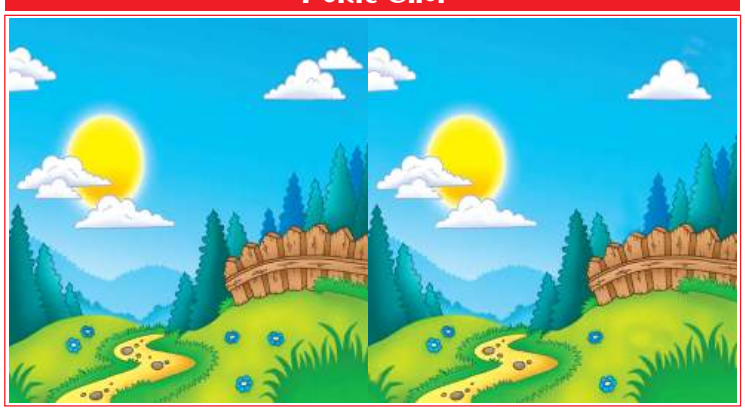

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड इत्यादि से लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी न करें। लेनदारी वसूल करने के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी।

वृषभ

नई आर्थिक नीति बन सकती है। कार्यस्थल पर सुधार व परिवर्तन से भविष्य में लाभ होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पार्टनरों का सहयोग कार्य में गति प्रदान करेगा।

मिथुन

व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। शत्रु सक्रिय रहेंगे। नौकरी में उन्नति होगी। निवेशादि करने का मन बनेगा।

कर्क

धनागम होगा। प्रतिद्वंद्वी अपना रास्ता छोड़ देंगे। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। किसी भी प्रकार के झगड़ों में न पड़ें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

सिंह

रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सभी ओर से खुश खबरें प्राप्त होंगी। पारिवारिक चिंता रहेगी। अज्ञात भय सताएगा।

कन्या

ऐश्वर्य के साधनों पर व्यय होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। आय में निश्चितता रहेगी।

तुला

लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में संतोष रहेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। बेचैनी रहेगी।

वृश्चिक

किसी अपरिचित व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। पुराना रोग उभर सकता है।

धनु

व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रयास सफल रहेंगे। पराक्रम बढ़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शेयर मार्केट मनोनुकूल लाभ देंगे।

मकर

घर में अतिथियों का आगमन होगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होगा। बाहर जाने का मन बनेगा। जल्दबाजी न करें।

कुम्भ

अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। सुख के साधनों पर व्यय होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

मीन

व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। हल्की हंसी-मजाक न करें।

बंटवारा 1947 को मिली हरी झंडी 14 अगस्त को थिएटर्स में देगी दस्तक

बॉलीवुड | मसाला

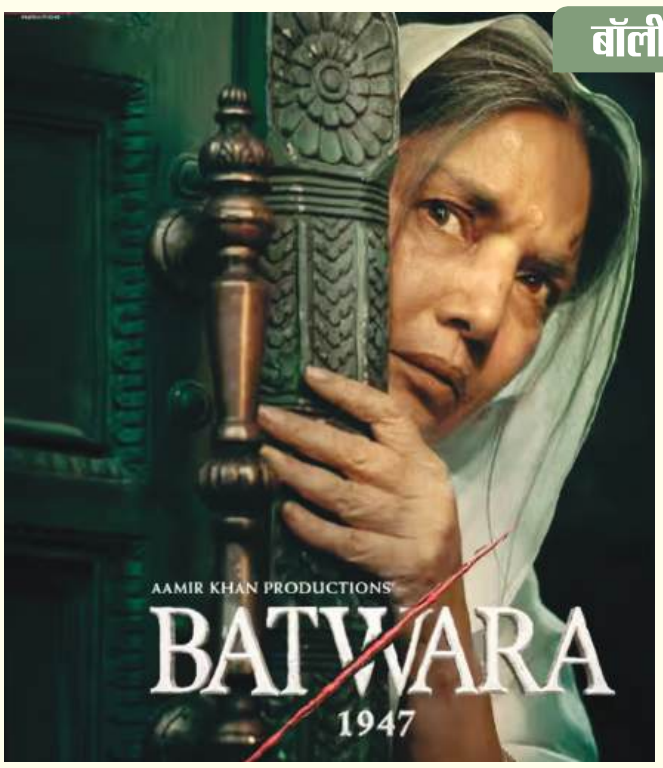

सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म बंटवारा:1947 की रिलीज की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, प्रशंसकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। फिल्म के दो टीजर और एक गाना पहले ही सामने आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है।

सर्टिफिकेशन ने भी फिल्म को हरी झंडी दे दी है। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कितने कट लगाए हैं और इसे कौन-सा सर्टिफिकेट मिला है, आइए जानते हैं पूरी डिटेल।

रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी स्टारर फिल्म बंटवारा:1947 को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास कर दिया है। फिल्म देखने के बाद बोर्ड ने मेकर्स को इसमें किसी भी तरह के बदलाव या दृश्य हटाने के निर्देश नहीं दिए हैं।

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत के बहुचर्चित नाटक जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्या ही नई पर आधारित है। 1947 के विभाजन की संवेदनशील पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म बंटवारे के बाद हुए दंगों और भारतीय उपमहाद्वीप में फैली गहरी भावनात्मक उथल-पुथल को दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक मुहाजिर परिवार पर आधारित है, जो विभाजन के बाद लाहौर जाकर एक खाली पड़े हिंदू घर में रहने लगता है।

कहानी की मुख्य धुरी एक बुजुर्ग हिंदू महिला है, जो विभाजन के उस कठिन दौर में भी अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। फिल्म इस बुजुर्ग महिला और मुहाजिर परिवार के बीच पनपने वाले मानवीय रिश्तों, संवेदनाओं और वैचारिक संघर्षों को बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है।

बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा महा मुकाबला

फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो सनी देओल की यह फिल्म 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की सीधी टक्कर इमरान हाशमी की बहुचर्चित फिल्म आवारापन-2 से होगी, जो उसी दिन रिलीज हो रही है। ऐसे में इस वीकेंड दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश देखने को मिलने वाला है।

बॉलीवुड | मन की बात

छात्रों पर हो रही बर्बरता पर भड़कीं स्वरा भास्कर

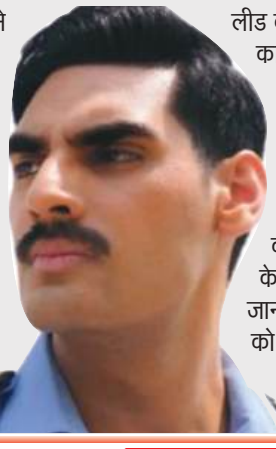

नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन से ब?ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं और इसे लगातार बॉलीवुड सेलेब्स का भी समर्थन मिल रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी कर रही हैं। वो स्टूडेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। अब उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ हो रही बर्बरता को लेकर भारत सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने पर संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में तैनात जवानों से उनकी झड़प हो गई थी और कई स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज भी किया गया था। स्टूडेंट्स पर हो रही बर्बरता पर स्वरा भास्कर ने भारत सरकार पर भड़कते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसमें एक्ट्रेस ने कहा, क्या आप ये जानते हैं कि जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर सरकार का रवैया कैसा है? उन्होंने दिल्ली पुलिस को खुली छूट दे रखी है। उनके पास क्रस्न है, CRPF की 20 कंपनियां हैं और अब वे कश्मीर से पैरामिलिट्री CRPF की 10 और कंपनियां भी बुला रहे हैं।एक्ट्रेस ने आगे कहा, स्टूडेंट्स शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने आगे सरकार की स्टूडेंट्स के खिलाफ तैयारी को देखते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान और चीन से भी ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स खतरनाक है? उन्होंने आगे कहा, भारत सरकार ने हमारे देश के युवाओं और बच्चों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये सच में शर्मनाक है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को स्वरा भास्कर के अलावा और भी कई मशहूर हस्तियों ने अपना समर्थन दिया है। इनमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, सोनू सूद, रितेश देशमुख, प्रीति जिंटा, प्रकाश राज, भूमि पेडनेकर, जेनेलिया देशमुख, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, दिलजीत दोसांझ आदि शामिल हैं।

जल्द ही हारर फिल्म में नजर आयेंगे अहान शेट्टी

बॉलीवुड | गपशप

अहान अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सेलेक्टिव हैं और अब जानकारी मिली है कि वो बहुत जल्द एक हॉरर फिल्म में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अहान विक्रम भट्ट की पॉपुलर फ्रेंचाइजी 1920 की छठवीं किस्त में नजर आने वाले हैं। इसका नाम 1920: कोल्ड विंटर है। हालांकि फिल्म अभी अपनी राइटिंग स्टेज पर है और विक्रम भट्ट और प्रोड्यूसर आनंद पंडित इसके स्क्रीनप्ले पर काम कर रहे हैं।

मिड-डे को एक सोर्स ने बताया कि यह प्रोजेक्ट अहान शेट्टी का सुपरनैचुरल जॉनर में पहला काम है। इससे पहले वो साल 2021 में आई रोमांटिक एक्शन-ड्रामा तड़प में काम कर चुके हैं। तड़प उनकी डेब्यू फिल्म भी थी।

फिलहाल मेकर्स उनके अपोजिट एक फीमेल लीड को कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं। वे इस रोल के लिए किसी न्यूकमर को कास्ट करने के बजाए एक जानी-मानी एक्ट्रेस को लेना चाहते है। अगर सबकुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू हो जाएगी।

फिल्म के कुछ सीन्स स्कॉटलैंड और कुछ शिमला में शूट होंगे। हॉरर जॉनर में कदम रखने से पहले, अहान अब डायरेक्टर टीनू देसाई की फिल्म सनकी में नजर आएंगे। 1920: कोल्ड विंटर के साथ, यह एक्टर अपनी फिल्मोग्राफी में एक नया आयाम जोड़ सकते हैं।

भारत का वो इकलौता शहर, जहां अंडा बेचना भी है जुर्म, सीधा जाना पड़ सकता है जेल

भारत में कई पवित्र और धार्मिक शहर हैं जैसे वाराणसी और ऋषिकेश। लेकिन गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालिताना ने एक ऐसा कदम उठाया जो दुनिया के किसी शहर ने नहीं लिया था। साल 2014 में यह दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया जहाँ मांस, मछली और अंडे की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। पालिताना शत्रुंजय पहाड़ियों पर बसा हुआ है जहाँ 900 से अधिक जैन मंदिर मौजूद हैं। साल 2014 में करीब 200 जैन साधुओं ने एक बड़ी भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग थी कि इस पवित्र तीर्थ स्थल के आसपास चल रही लगभग 250 कसाई की दुकानों को तुरंत बंद किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान खींचा और सरकार पर दबाव बढ़ गया। साधुओं के कड़े विरोध के बाद गुजरात सरकार ने पालिताना के भीतर मांस और अंडे की बिक्री और जानवरों के वध पर औपचारिक प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ अंडा बेचना भी एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए कानूनी सजा का प्रावधान है। यहाँ शाकाहार केवल एक पसंद नहीं बल्कि एक कानूनी अनिवार्यता बन चुका है। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुँचाना उनके धर्म के विरुद्ध है। पालिताना के जैन समुदाय के लिए यह प्रतिबंध केवल एक सरकारी नीति नहीं थी, बल्कि उनकी 2,500 साल पुरानी आस्था को आधिकारिक मान्यता मिलने जैसा था। उनके लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। इस बैन के बाद बहस भी शुरू हुई। भोजन की स्वतंत्रता के समर्थकों और पर्यटन पेशेवरों ने इस कदम की आलोचना की। उनका तर्क था कि सार्वजनिक शहर में खान-पान की पसंद पर रोक लगाना संवैधानिक दायरे का उल्लंघन है। गैर-जैन निवासियों और कामगारों ने अपनी आजीविका को लेकर भी चिंता जाहिर की, जो आज भी एक बहस का विषय है। आज भी पालिताना पृथ्वी का एकमात्र ऐसा शहर बना हुआ है जहाँ शाकाहार का पालन करना कानून है। यह शहर प्राचीन विश्वास और आधुनिक शासन के मेल का केंद्र है जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और विद्वानों को अपनी ओर खींचता है। चाहे लोग इस बैन के बारे में जो भी सोचें, लेकिन इस शहर ने अपनी थाली के जरिए इतिहास जरूर रच दिया है।

अजब-गजब

डिग्री मिलते ही हवा में क्यों उछाली जाती है टोपी

114 साल पुराना है टोपी को हवा में उछालने का इतिहास

आपने देखा होगा कि कॉलेज-यूनिवर्सिटियों के दीक्षांत समारोह (ग्रेजुएशन सेरेमनी) में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स गाउन पहनकर जाते हैं। डिग्री मिलने के बाद वे सब एक साथ खड़े होकर सिर पर सजी चौकोर टोपियों को हवा में उछालते हैं। यह रिवाज आजकल इतना आम हो चुका है कि लोगों को लगता है कि यह ग्रेजुएशन सेरेमनी की सामान्य परंपरा है। लेकिन सवाल है कि इस रिवाज की शुरुआत कहां से हुई और इसका असल में अर्थ क्या है। आज हम इसी परंपरा के पीछे छिपे दिलचस्प इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि सैकड़ों साल पुराना है। एक्सपर्टों के मुताबिक, दीक्षांत समारोहों के दौरान गाउन और कैप पहने जाने की परंपरा 12वीं-13वीं शताब्दी से जुड़ी है। उस वक्त यूरोप में पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी। उस दौरान बोलोग्ना विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे संस्थान यूरोप में हायर एजुकेशन के अहम केंद्र बन गए थे।

उन दिनों, जिन विश्वविद्यालयों की इमारतें बहुत ठंडी होती थीं। उनके कमरों को गर्म रखने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं होती थी। ऐसे में खुद को गर्म रखने के लिए वहां के छात्र और प्रोफेसर पढ़ाई के दौरान लंबी पोशाकें पहनते थे। इन पोशाकों से गले, सिर और पैरों को ढंका जाता था। वे जूते भी पहनते थे, जिससे पैरों को ठंड न लगे। रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौर में कई सारे विद्वान पादरियों से भी जुड़े हुए थे। इसलिए उनके कपड़े चर्च के अधिकारियों की ओर से पहने जाने वाले गाउन जैसे कपड़ों से मिलते-जुलते थे। धीरे-धीरे कपड़ों का यह व्यावहारिक उपयोग ग्रेजुएशन सेरेमनी के प्रतीक के रूप में बदल गया। इसके बाद यूरोप के विश्वविद्यालयों ने इस पोशाक को अनिवार्य बनाने के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए। जिसके बाद दीक्षांत समारोहों में गाउन, हुड और कैप कंपलसरी कर दिए गए। दीक्षांत समारोह की पोशाक में हुड सबसे हिस्सा माना गया। आसान शब्दों में कहें तो यह गाउन के ऊपर गले में पहना जाने वाला एक विशेष कपड़ा या स्कार्फ होता है, जो पीछे की तरफ पीठ पर लटकता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी में हुड के अलग-अलग रंगों, डिजाइनों और आकारों से यह तय होने लगा कि छात्र किस शैक्षणिक क्षेत्र से है और उनकी शिक्षा का स्तर बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी क्या है। यूरोपियन देशों ने बाद में एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के सैकड़ों

देशों को अपना गुलाम बनाया और वहां पर अपना एजुकेशन सिस्टम थोंपा। इसलिए यूरोप से निकलकर यह ड्रेस उन देशों में भी दीक्षांत समारोह की वेशभूषा के रूप में स्थापित हो गई।आज के दौर में कॉलेजों में इन गाउनों को खुद को गर्म रखने के लिए नहीं पहना जाता। इसके बावजूद, दुनिया के तमाम देशों में यह प्राचीन परंपरा आज भी पूरी तरह जीवंत है।

अब सवाल आता है कि दीक्षांत समारोह के अंत में टोपियां हवा में क्यों उछाली जाती हैं। इस रिवाज के पीछे एक आधुनिक परंपरा मानी जाती है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत 1912 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से हुई थी। उस वर्ष ग्रेजुएशन करने वाले नौसेना के कैडेटों को उनकी पढ़ाई पूरी होने पर नई टोपियां सौंपी गई। चूंकि इसके बाद उन छात्रों को पुरानी टोपियों की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुशी में उन्हें हवा में उछाल दिया।

धीरे-धीरे यह प्रथा अमेरिका के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फैल गई। इसके बाद यह परंपरा दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। आज के दौर में अधिकतर दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स अपनी टोपी हवा में उछालकर खुशी जताते हैं। हालांकि, हर संस्थान इस प्रथा को बढ़ावा नहीं देता। कई इंस्टिट्यूट्स टोपियों के खोने या खराब होने से बचाने के लिए ऐसा करने से मना करते हैं।

शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाया जाए : राहुल गांधी

» नीट पेपर लीक मामले पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन तेज

» राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसद गांधी स्मृति तक कर रहे मार्च

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले पर इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसद गांधी स्मृति तक मार्च कर रहे हैं, जहां वे पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देंगे। विपक्ष ने सरकार पर छात्रों के साथ खड़े होने और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग करते हुए कहा, भारत के छात्र अकेले नहीं हैं।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन के सांसदों के एक दल के साथ तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति जा रहे हैं। गांधी ने कहा कि वे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिनकी जान नीट पेपर लीक के बाद चली गई थी। उन्होंने कहा कि अभी, इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्ण ढंग से तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति जा रहे हैं।

नीट यूजी पेपर लीक के बाद जान देने के लिए मजबूर हुए छात्र

हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया, वे बच्चे जिन्हें नीट यूजी पेपर लीक के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल हैं - जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से न्याय और जवाबदेही की मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं हैं। पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है।

सरकार डरी है इसलिए बैरिकेड्स लगा दिए : राजीव शुक्ला

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि हम सब गांधी स्मृति की ओर जा रहे हैं वे डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हम जहाँ भी जाएँ, यह देश हमारा है। ये लोग पुलिस बुलाकर हमें डरा-धमका रहे हैं। हम इससे डरते नहीं हैं। RJD सांसद संजय यादव ने कहा कि पिछले 10 सालों में 152 बार पेपर लीक हुए हैं, और किसी को भी सज़ा नहीं हुई है। शिक्षा व्यवस्था में कोई पारदर्शिता नहीं है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कानूनी नोटिस भेजूंगा : के टीआर

» परीक्षा गड़बड़ी में नाम घसीटने पर छिड़ी कानूनी जंग

» बीआरएस ने कांग्रेस सरकार को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने तेलंगाना के सीएम ए. रेवंत रेड्डी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उन झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि करने वाले आरोपों के सिलसिले में भेजा गया है जिनमें उन्हें ग्लोबाएरेना टेक्नोलॉजीज से जोड़ा गया था। इस कंपनी का मूल्यांकन सॉफ्टवेयर 19 के तेलंगाना इंटरमीडिएट नतीजों की जांच के दौरान जांच के दायरे में आया था।

टिस में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने, विवादित बयानों को वापस लेने और भविष्य में ऐसे आरोप न दोहराने का वादा करने की मांग की गई है। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान कई बेबुनियाद आरोप लगाए और बाद में सोशल मीडिया व अन्य सार्वजनिक मंचों पर उन्हें और हवा दी, जबकि अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। नोटिस के अनुसार, इन बयानों को बड़े पैमाने पर फैलाया गया, जिससे की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को गंभीर नुकसान पहुँचा।

सीएम रेड्डी आरोपों को बताया गलत

इस नोटिस में सीएम रेड्डी के उन आरोपों को खास तौर पर गलत बताया गया है जिनमें कहा गया था कि ग्लोबारेना, के टीआर की बेनामी कंपनी है, कि उन्होंने कथित अदालती निर्देशों के बावजूद कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की, कि उन्होंने कंपनी के पक्ष में अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया कि उन्होंने कंपनी को परीक्षा से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद की, कि उन्होंने राजनीतिक संपर्कों के जरिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में प्रभाव डाला और वे उस निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार थे।

यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से

» आज लगेगी खिलाड़ियों की बोली

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

आगरा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट को आईपीएल स्तर का नया मंच देने के लिए यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन शुरू होने जा रहा है। लीग की शुरुआत 14 अगस्त को लखनऊ के इकाना स्टेडियम से होगी और फाइनल मैच छह सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। यूपी टी20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लीग मुख्य रूप से लखनऊ और कानपुर में खेली जाएगी।

इसके बाद फार्मेट बदलकर दूसरे शहरों में भी मैच कराए जाएंगे। पूरा आयोजन आइपीएल की तर्ज पर होगा, जिससे दर्शकों को आइपीएल जैसा अनुभव मिलेगा। लीग के लिए शुक्रवार लगने वाली बोली में आक्शनर अंगद बेदी होंगे। इसमें 2500 खिलाड़ियों से अधिक पर बोली लगेगी। 100 खिलाड़ी पांच लाख रुपये में, 45 खिलाड़ी साढ़े तीन लाख रुपये में और बाकी खिलाड़ी ढाई लाख रुपये में फ्रेंचाइजी खरीदेंगी। जिसमें गोरखपुर लायंस के पास 55.90 लाख, नोएडा सुपर किंग्स के पास 80.60 लाख , मेरठ मावरिक्स के पास 28.70 , लखनऊ फाल्कंस के पास 30.20 लाख रूपये रखें हैं ।

धर्मेन्द्र प्रधान से जुड़े मंत्रालयों के कार्यकलापों की स्वतंत्र जांच हो : अमिताभ ठाकुर

» आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीम को भेजा प्रतिवेदन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने प्रधानमंत्री को एक प्रतिवेदन भेजकर केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के कार्यकाल में उनके अधीन रहे मंत्रालयों के कार्यकलापों की स्वतंत्र प्रशासनिक जांच कराने का अनुरोध किया है।

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि नीट-यूजी 24 परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं, उसके बाद हुई आपराधिक जांच, सर्वोच्च न्यायालय में हुई कार्यवाही तथा केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन से शिक्षा व्यवस्था की संस्थागत जवाबदेही एवं निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। धर्मेन्द्र प्रधान के कौशल विकास मंत्री के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के कार्यकाल में मंत्रालय के गोपनीय अभिलेखों के लीक होने की घटना, तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर सीएजी की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है। इन सभी तथ्यों के संबंध में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रशासनिक तथ्य-पड़ताल कराने का अनुरोध किया गया है।

> “नीट-यूजी 24 परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं, उसके बाद हुई आपराधिक जांच, सर्वोच्च न्यायालय में हुई कार्यवाही तथा केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन से शिक्षा व्यवस्था की संस्थागत जवाबदेही एवं निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठे हैं।”

हार के बावजूद भारत रैंकिंग में शानदार

» शुभमन गिल नंबर 2 पर, जो रूट की टॉप 10 में वापसी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल और जो रूट की लंबी छलांग व्यक्तिगत प्रदर्शन की निरंतरता को उजागर करती है, भले ही भारतीय टीम को श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा हो। कुलदीप यादव का शीर्ष दस से बाहर होना और अक्षर पटेल की रैंकिंग में सुधार यह विश्लेषण करता है कि भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में वर्तमान में स्थिरता और पैनापन लाने की आवश्यकता है।

इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर भारतीय बल्लेबाजों को आईसीसी की ताजा रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर बल्लेबाजों की सूची में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली हैं। बता दें कि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल अभी भी 802 रेटिंग अंकों के साथ एकदिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने लगातार उपयोगी पारियां खेलीं, जिसके बाद वह 801 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष स्थान से सिर्फ एक अंक पीछे पहुंच गए हैं। गिल ने एजबेस्टन में 80 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होने से पहले शानदार बल्लेबाजी की थी। इसके बाद उन्होंने कार्डिफ में 31 और लॉर्ड्स में 77 रन की पारी खेली थीं।

कोहली व रोहित में भी सुधार

विराट कोहली को भी इस श्रृंखला का लाभ मिला हैं। उन्होंने तीन मुकाबलों में दो अर्धशतक लगाए और अब उनके 767 रेटिंग अंक हो गए हैं। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में 138 रन की बेहतरीन शतकीय पारी खेली, जिससे उनकी रेटिंग 758 अंक तक पहुंच गई हैं। गौरतलब है कि आईसीसी की शीर्ष चार बल्लेबाजों की सूची में अब तीन भारतीय खिलाड़ियों का शामिल होना भारतीय बल्लेबाजी की मजबूती को दर्शाता है।

गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत को झटका

गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत को झटका लगा हैं। कुलदीप यादव, जो पहले शीर्ष 10 में शामिल थे, इस श्रृंखला में एक भी मैच नहीं खेल पाए और अब 11वें स्थान पर खिसक गए हैं। जसप्रीत बुमराह एक स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अर्शदीप सिंह तीन स्थान नीचे संयुक्त 30वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि अक्षर पटेल ने 10 स्थान की छलांग लगाकर 32वां स्थान हासिल किया है।

प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार कर रही है नरेन्द्र मोदी सरकार: सोनिया गांधी

» कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख ने भाजपा पर साधा निशाना

» अंग्रेजी दैनिक 'द हिंदू' के लिए लिखा लेख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नयी दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा व्यवस्था के 'पतन' के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों को नरेन्द्र मोदी सरकार 'देश के शत्रु' की तरह पेश कर रही है और उनकी आवाज दबाने के लिए दमनकारी ताकत का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने अंग्रेजी दैनिक 'द हिंदू' के लिए लिखे लेख में यह भी कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगें सीधी और स्पष्ट हैं कि भारत सरकार की जवाबदेही तय हो और शिक्षा में सुधार किया जाए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ''मोदी सरकार ने उनकी बहादुरी का जवाब कायरता और निर्मम क्रूरता से दिया है, उनके साथ भविष्य के कर्णधारों की तरह नहीं, बल्कि देश के शत्रुओं की तरह व्यवहार किया है।'' उन्होंने 20 जुलाई की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ''शर्मनाक दिन'' था, जब दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ''बिना किसी उकसावे के हिंसा'' का सहारा लिया।

सोनिया गांधी ने दावा किया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा पर कुल बजट में खर्च का अनुपात क्रमशः 5० प्रतिशत और 33 प्रतिशत कम हुआ है। उन्होंने सवाल किया, ''क्या कोई इस तरह के बेतुके तरीके से पीछे हटने में कोई तुक देख सकता है?'' उन्होंने पिछले 12 वर्षों में करीब एक लाख सरकारी स्कूल बंद किए जाने और 43,000 निजी स्कूल खोले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन निजी स्कूलों में से बड़ी संख्या में स्कूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उससे जुड़े संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान में कटौती की और उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए मजबूर किया गया।

संवाद के बजाय हिंसा का इस्तेमाल करती है सरकार

सोनिया गांधी ने लिखा, 'इसने हमारी सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार 'नियमित रूप से संवाद के बजाय हिंसा का इस्तेमाल करती है'' और किसानों से लेकर कार्यकर्ताओं तक, असहमति को दबाने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति दिखायी देती है। सोनिया गांधी ने लिखा, 'हमारे भविष्य के डॉक्टरों और इंजीनियरों, शिक्षकों और लोक सेवकों, उद्यमियों और राष्ट्र निर्माताओं तक पहुंचने और उन्हें समझने के बजाय, सरकार ने उनके खिलाफ राज्य की दमनकारी शक्ति का इस्तेमाल किया।' उन्होंने कहा कि इसे 'न तो माफ किया जा सकता है और न ही भुलाया जा सकता है।' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने 'हर असहमति को राष्ट्र-विरोधी बताने वाले पुराने टूलकिट' का इस्तेमाल किया है।

निजी शिक्षा हासिल करने की लागत लाखों प्रतिभाशाली छात्रों को कर रही हतोत्साहित

सोनिया गांधी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और सस्ती सार्वजनिक शिक्षा की कमी के कारण भारतीय परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा पर अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की कोचिंग पर परिवारों द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि उतनी है, जितना मोदी सरकार सार्वजनिक शिक्षा पर कुल मिलाकर निवेश करती है। उन्होंने लिखा, 'निजी शिक्षा हासिल करने की लागत लाखों प्रतिभाशाली छात्रों को हतोत्साहित करती है, जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन उनमें अपार क्षमता होती है।' सोनिया गांधी ने कहा कि इन खर्चों से छात्रों पर परिवारों की उम्मीदों का 'कुचल देने वाला बोझ' भी पड़ता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने परीक्षा प्रणाली में 'केंद्रीकरण, निजीकरण और राजनीतिकरण' का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

सोनिया गांधी ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में 152 प्रश्नपत्र लीक हुए हैं, जिनमें 17 में एनटीए के गठन के बाद उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में नौ कथित प्रश्नपत्र लीक भी शामिल हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि ''पक्षपातपूर्ण निष्ठा'' के आधार पर अयोग्य कुलपतियों की नियुक्ति और राजनीतिक रूप से जुड़े लेकिन अयोग्य शिक्षकों की भर्ती ने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षण का संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा व्यवस्था बदलते तरीकों और मानकों के साथ कदम नहीं मिला पा रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित दुनिया की जरूरतों के अनुरूप ढलने में विशेष रूप से असमर्थ है।उनका कहना है, ''छात्रों को एक ऐसी व्यवस्था में सफल होने की कोशिश करनी पड़ रही है जिसकी मांगें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि वे स्वयं इसके लिए पर्याप्त संसाधनों से बहुत दूर हैं।

12 वर्षों में देशभर में 152 प्रश्नपत्र लीक हुए

संयुक्त परिवार पर सुप्रीम टिप्पणी, कहा माता-पिता की जगह ले रहा मोबाइल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संयुक्त परिवार प्रणाली के लगातार खत्म होने और एकल परिवारों में बच्चों को समय देने के बजाय मोबाइल-गैजेट्स थमा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि माता-पिता की जगह गैजेट्स (मोबाइल) ले लेंगे, तो यह स्थिति समाज के लिए विनाशकारी साबित होगी और आने वाली पीढ़ी पारिवारिक रिश्तों व बंधनों से पूरी तरह अनजान हो जाएगी।

दरअसल, हाल ही में पति-पत्नी की हत्या की घटनाओं में, जिनमें सोनम रघुवंशी का मामला भी शामिल है, इसका विश्लेषण करते हुए स्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि यह बदलते समाज का प्रतिबिंब है। पीठ ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी अधिक बुद्धिमान और जानकार है, लेकिन आज की पीढ़ी अत्यधिक दबाव झेलने में सक्षम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल लोग व्हाट्सएप पर प्रसारित संदेशों पर भरोसा करते हैं और उन्हें ज्ञान मान लेते हैं। अदालत की चिंता से सहमत होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक सामाजिक समस्या बन गई है और मानवीय संबंधों में विश्वास कम हो रहा है तथा सहिष्णुता की कमी हो रही है।

यह एक आपदा है

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि हाल ही में वे एक रेस्तरां में थे और उन्होंने देखा कि एक परिवार ने खाना खाते समय बच्चे को व्यस्त रखने के लिए उसे फोन दे दिया। उन्होंने कहा, अगर माता-पिता की जगह गैजेट्स ने ले ली, तो यह एक आपदा है। भविष्य में ऐसा और भी ज्यादा होगा। संयुक्त परिवार एक संपत्ति है, और लोग इसे समझते नहीं हैं। खुशी भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि मानवीय बंधन और रिश्तों से मिलती है। हम मशीनों की तरह होते जा रहे हैं।

दिल्ली, यूपी-पंजाब में कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी

450 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी का मामला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी के बुलंदशहर, दिल्ली और पंजाब में एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की जा रही है।

इडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से की जा रही इस कार्रवाई में संतोष ओवासीज और उससे जुड़ी कंपनियों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी के मामले पर आधारित है। आरोप है कि संतोष ओवासीज ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से करीब 45० करोड़ रुपये का ऋण लिया। ऋण राशि का निर्धारित उद्देश्य के विपरीत दुरुपयोग किया गया। इससे बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

भारी हंगामें के बीच लोस 27 तक स्थगित, राज्यसभा की कार्यवाही थमी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है। आज भी नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित क दिया गया। वहीं, राज्यसभा में इस चर्चा जारी है।

» संसद से सड़क तक हंगामा जारी

विपक्ष के नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब लोकसभा की अगली बैठक 27 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे होगी।

हम चर्चा नहीं करेंगे, तो देश में नहीं जाएगा सही संदेश : रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैंने आज एक बार फिर केसी वेणुगोपाल जी से अनुरोध किया है कि जब हम सभी इस बात से सहमत हैं कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए, तो हमें चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और चर्चा की मांग की है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देश में सही संदेश नहीं जाएगा।

विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में शामिल हुए खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान और अटूट साहस को याद करते हुए उन्हें नमन किया।

महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी **4** पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा**
द्वारा **आस्था प्रिंटर्स**, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक- संजय शर्मा**